अमर उजाला

प्रवाह

नई दिल्ली । शनिवार, 6 जुलाई 2019

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पृथ्वी पर बदलाव लाने के लिए साहस और प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
- बराक ओबामा

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

आर्थिक विवशता और मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संतुलन बिठाने की कमोबेश कोशिश की है, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये उपाय अर्थव्यवस्था को गति देने में सफल होंगे

संतुलन साधने की कोशिश

निर्मला सीतारमण का पहला बजट सिर्फ पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने या ब्रीफकेस की जगह 'बही-खाते' के साथ आने के कारण ही यादगार नहीं था, बल्कि उनकी एकाधिक घोषणाएं चुनौतियों से निपटते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने की संजीदगी के बारे में बताती हैं। चाहे वह एमएसएमई क्षेत्र के लिए 350 करोड़ का आवंटन हो, एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के लिए पैकेज की घोषणा हो या स्टार्ट अप्स को एंजेल टैक्स से दी गई राहत, ये बताती हैं कि समस्याओं के समाधान पर सरकार की नजर है। इलेक्ट्रिक वाहनों और डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन, 'वन नेशन-वन कार्ड' और उच्च शिक्षा पर फोकस अगर सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं के उदाहरण हैं, तो टैक्स रिटर्न के समय पैन न होने पर आधार के उपयोग को मंजूरी एक बेहद व्यावहारिक कदम है। आधारभूत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला भी उचित है, जिससे रोजगार के क्षेत्र में लाभ होगा। अलबत्ता आंकड़ों और आवंटन के मामले में चुप्पी हैरान करने वाली है, क्योंकि बजट का मूल्यांकन अंततः विभिन्न मदों में किए जाने वाले आवंटनों और अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों के आधार पर ही होता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हो, तब रक्षा क्षेत्र में आवंटन के बारे में न बताना समझ में नहीं आता। ऐसे ही, बजट में रोजगार का रोडमैप बताकर सरकार बेरोजगारी के क्षेत्र में व्याप्त चिंताओं का समाधान कर सकती थी। कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, उच्च शिक्षा और महिलाओं की बेहतरी की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ उम्मीदें भी जगाते हैं, लेकिन समग्रता में वे किसी साहसी नजरिये का सुबूत नहीं देते। इसकी बड़ी वजह सरकार की आर्थिक विवशता भी है। फंड की कमी होने के कारण उसके सामने प्राथमिकताएं तय करने की चुनौती है। पेट्रोल-डीजल महंगा करने के पीछे सरकार की यह आर्थिक विवशता ही काम कर रही है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन तेल महंगा होने और राजस्व संग्रह उम्मीदों के अनुरूप न होने की स्थिति में राजकोषीय घाटा लक्ष्य से अधिक हो सकता है। कुल मिलाकर, मौजूदा परिस्थितियों में यह बजट अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे, रोजगार में बढ़ोतरी करे और आर्थिक अनुशासन बरकरार रखे, तो यह भी कम नहीं होगा।

एनडीए-2 की लय बनाता बजट

आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 2019 के बजट में ऐसे कार्यक्रमों की निरंतरता बनाए रखी गई है, जिनसे सभी भारतीयों की बुनियादी सुविधाओं तक 2022 तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो पहला बजट पेश किया है, उसमें जीवन-यापन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय खर्च के प्रावधान किए गए हैं। इसमें आवास, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, गैस स्टोव, स्वच्छता आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही अगले पांच वर्षों के दौरान आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सौ लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। एनडीए सरकार के शासन के मंत्र 'रिफॉर्म, परफॉर्म ऐंड ट्रांसफॉर्म इंडिया' (सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण) के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण उद्यम हैं।

इस बजट में उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की अग्रणी प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें देश में रहकर ही सेवा करने के लिए प्रेरित करने का काम करेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना बिलकुल समय के साथ की गई है। मुख्यतः पर्याप्त गुणवत्तायुक्त अनुसंधान उत्पादन की कमी के कारण पिछले वर्षों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में खास प्रगति नहीं हुई है। संस्थाओं में और अधिक स्वायत्तता लाने के लिए उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना से बेहतर अकादमिक नतीजे हासिल करने में मदद मिलेगी।

बजट में जीवन यापन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय खर्च के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि गुणवत्तायुक्त रोजगार सृजन पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत थी।

मोहन दास पई, प्रमुख, एरियन कैपिटल

निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में जो व्यापक सुधार प्रस्तुत किए हैं, उनमें सबसे अधिक ध्यान वित्तीय क्षेत्र की ओर केंद्रित किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी का जो परिदृश्य है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की मजबूत पूंजी दी गई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) की जमा संपत्ति खरीदने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कुल एक लाख करोड़ रुपये की राशि के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10 फीसदी तक के नुकसान पर एक बार छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी। इससे पिछले वर्ष एनबीएफसी पर छाए संकट के कारण छोटे कारोबारों को कर्ज लेने में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। विशाल कॉरपोरेट बांड मार्केट का निर्माण कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच बढ़ाएगा जिससे निवेश आधारित विकास को गति मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, इसके बावजूद इसका इस क्षेत्र पर सीमित अधिकार है। इसलिए एनबीएफसी को लेकर वित्त विधेयक में रिजर्व बैंक के नियामक प्राधिकार को मजबूत करने के लिए उचित प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। एक साहसिक और प्रभावशाली कदम उठाते हुए वित्त मंत्री बाह्य बाजारों में बाहरी मुद्राओं से एक संप्रभु उधार कार्यक्रम शुरू करेंगी, जिससे बाजार में बहुत जरूरी तरलता आएगी और खपत बढ़ेगी।

विमानन, मीडिया और बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए आसान मानदंड और एफपीआई (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट) के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाना विनिवेश के अवसरों और बाहरी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक था। व्यापारिक लेन-देन में रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना किए जाने वाले नकद भुगतान पर अंकुश लगाने के प्रयास के साथ, एनडीए सरकार के लिए डिजिटलीकरण प्राथमिकता बना हुआ है। हालांकि एक विरोधाभास यह भी है कि सरकार ने एक ओर तो कर भुगतान में बेईमानी करने वालों को हतोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं दो और पांच करोड़ रुपये की आय वाले ईमानदार करदाताओं पर क्रमशः दस फीसदी और पंद्रह फीसदी का सरचार्ज लगाकर एक तरह से उन्हें दंडित करने का काम भी किया है।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर बजट में और अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत थी वह है गुणवत्ता युक्त रोजगार का सृजन। रोजगार सृजन और देश के किसानों की आय बढ़ाना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके साथ ही भारत के जनसांख्यिकी रुझान को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसकी रूपरेखा दो दिन पहले आई आर्थिक समीक्षा में दी गई है। सुदृढ़ विकास दिखाने वाले क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता, दीर्घकालिक नौकरियों का विकास किया जाएगा। फोकस भारत की बड़ी कंपनियों को बढ़ाने और नए जमाने के 'टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स' को प्रोत्साहित किए जाने पर होना चाहिए। एजेंल टैक्स एक उत्पीड़न ही था, वित्त मंत्री ने इसे एआईएफ (अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड) कैटेगरी एक और दो निवेशकों पर से इसे हटाने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि इस उत्पीड़न को हटाए जाने को स्टार्टअप्स के लाभ के तौर पर नहीं देखा जा सकता। स्टार्टअप के निवेश और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

ऐसे उच्च जोखिम और कम तरलता वाले निवेशकों पर शेयर बाजार के निवेशकों की तरह का कर नहीं लगाया जा सकता, जो कि कम जोखिम और उच्च तरलता की स्थिति का लाभ उठाते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ को 20 फीसद से 10 फीसद तक नीचे लाने से स्टार्टअप्स के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर भुगतान, दीर्घकालिक रोजगार पैदा होगा। इस उपाय की अनदेखी की गई है।

सरकार 44 श्रम कानूनों से उत्पन्न जटिलताओं को दूर करने के लिए इन्हें चार व्यापक श्रम संहिता के रूप में समायोजित करने जा रही है। इससे व्यवसायों द्वारा अनुपालन लागतों को कम करने और श्रम की औपचारिकता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे वेतन में समरूपता आ सकेगी। यह बजट निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया सराहनीय प्रयास है, जिसमें सभी सुधारों पर विचार किया गया है और उन्होंने उन सारे मुद्दों पर ध्यान दिया है, जिनका सामना आज भारत कर रहा है।

रोजगार बढ़ाने के मुद्दे पर खामोशी

वित्त मंत्री के बजट भाषण का पूरे देश को इंतजार रहता है, क्योंकि उसी के जरिये देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। इस लिहाज से देखें, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण लंबा होने के बावजूद तथ्यों के लिहाज से बहुत स्पष्ट नहीं था। अर्थशास्त्रियों और आर्थिक विश्लेषकों को भाषण से ज्यादा अर्थव्यवस्था से जुड़े ठोस तथ्यों की जानकारी चाहिए होती है। वित्त मंत्री के बजट भाषण का 70 फीसदी हिस्सा पिछले साल की आर्थिक उपलब्धियों पर केंद्रित था। मौजूदा वित्त वर्ष के बारे में बाकी 30 फीसदी बातें उन्होंने कहीं, लेकिन उनमें भी आवंटनों का कोई जिक्र ही नहीं था। जबकि आवंटन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुश्किल यह भी है कि सरकार की उपलब्धियों को ही बजट भाषण में ज्यादा जगह दी गई। वित्त मंत्री ने शौचालय निर्माण के क्षेत्र में सरकार की सफलता का जिक्र किया। इसमें कोई शक नहीं कि शौचालय निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में सरकार का कामकाज बेहद उल्लेखनीय है। आखिर स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देकर ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन बेरोजगारी के बारे में बजट में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। ऐसे ही वित्त मंत्री ने बैंकों की गैरनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी आने की बात कही, लेकिन इस बारे में बहुत खुलकर कुछ नहीं कहा। बजट में उच्च

बादल मुखर्जी

अर्थशास्त्र के प्रोफेसर

बजट में उच्च शिक्षा पर फोकस किया गया है, जो अच्छी बात है, पर शोध का स्तर सुधारने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला क्या वांछित नतीजा दे पाएगा?

शिक्षा को महत्व देने की बात कही गई। यह अच्छी बात है, क्योंकि उच्च शिक्षा की ठोस बुनियाद ही रोजगार समेत दूसरे क्षेत्रों में हमारी स्थिति मजबूत करती है। बजट भाषण में इसका हवाला दिया गया कि दुनिया भर के 200 बेहतरीन उच्च शिक्षा संस्थानों में तीन हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें दो आईआईटी हैं और एक बंगलूरू का बेहद प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) है। लेकिन दो सौ में मात्र तीन हमारे संस्थानों का होना गर्व से ज्यादा चिंता की बात है। करोड़ों की युवा आबादी में इन तीन संस्थानों से निकले कुछ हजार युवाओं से भला कितना बदलाव आएगा? अब शोध का स्तर सुधारने के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही गई है। जबकि सच कहें, तो कमेटियों के गठन की सूचना से ही मुझे डर लगता है, क्योंकि इससे सार्थक कुछ होता नहीं। इस कमेटी में सरकार के लोगों का वर्चस्व होगा और अकादेमिक क्षेत्र के लोगों को कम महत्व दिया जाएगा। ऐसे में, क्या नतीजा निकलेगा, इस बारे में अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यह बजट इतना तो बताता ही है कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार कोई बहुत सुखद स्थिति में नहीं है। रोजगार बढ़ाना समय का तकाजा है, लेकिन उसके लिए बजट कोई व्यापक अवसर मुहैया नहीं कराता। ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा, पर वह काफी नहीं है। कृषि क्षेत्र पिछले कुछ समय से परेशानियों से गुजर रहा है। इस बजट में ग्रामीण उद्योग में 75,000 हुनरमंद उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन एमएसमई क्षेत्र के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन बहुत ही कम है। सरकार ने इस साल सौ करोड़ रुपये से अधिक के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। लेकिन विनिवेश सरकार के चाहने भर से नहीं होता। तिस पर ओएनजीसी और एयर इंडिया के हाल को देखते हुए यह लक्ष्य पूरा होना और कठिन लगता है। बीमार और बदतर कंपनियों का विनिवेश करने के लिए नियम और शर्तों में बदलाव करने पड़ते हैं। लेकिन सरकार की ओर से विनिवेश के मोर्चे पर ऐसी गंभीरता अभी तक तो नहीं देखी गई है।

केवल आंकड़े हैं खुश करने वाले

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। कॉरपोरेट को आयकर में छूट दी गई है। महिलाओं का ध्यान रखने के साथ ही किसानों को केंद्रीय बिंदु में रखने की बात कही। समस्या यह है कि आप जब सबको खुश करने की कोशिश में लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं। वित्त मंत्री ने अपने दो घंटे पंद्रह मिनट के भाषण में दो घंटे तो यही बताने में बिता दिया कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। पर आखिरी के दो मिनट में बताया कि पेट्रोल-डीजल पर सेस बढ़ा दिया गया है, जिससे अब सरकार को हर लीटर डीजल-पेट्रोल पर एक-एक रुपया ज्यादा मिलेगा। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अभी कम हैं, लेकिन जब यह बढ़ेंगी, तो सरकार की सारी गणना असफल हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले चार साल में पचास खरब डॉलर की हो जाएगी। इसमें तीन अनुमान लगाए गए हैं- एक तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आठ फीसदी की दर से बढ़ेगा। दूसरा मुद्रास्फीति चार फीसदी की दर से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात रुपया और डॉलर के बीच का अनुपात जो अभी लगभग सत्तर है, जो 2025 तक पचहत्तर डॉलर हो जाएगा। ये तीनों अनुमान क्या वास्तव में सच हैं? मुझे तो लगता है, नहीं। पहले ही सरकार ने कहा था कि इस वर्ष जीडीपी की वृद्धि दर सात से साढ़े सात फीसदी के बीच रहेगी। फिर कम करके साढ़े छह कर दिया, अब कह रहे हैं सात फीसद हो जाएगा। यह तो समय बताएगा कि क्या सच में अच्छे दिन आ रहे हैं। सरकार की बचत पिछले छह साल में आठ फीसद कम हो गई है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में बताया गया है कि, पिछले आठ साल में निवेश लगातार गिर रहा है, पर उम्मीद है अब इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। मगर यह गिर भी सकता है! निवेश क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लोगों की बचत नहीं हो पा रही है। इसका प्रमुख कारण है उत्पादन क्षमता घट रही है, रोजगार नहीं हैं। मनरेगा का बजट 61 हजार करोड़ था, जिसे कम करके 60 हजार करोड़ कर दिया गया। निर्धारित लागत में भी कमी कर दी गई। श्वेत क्रांति के नाम पर घोषणा तो की गई है कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देंगे पर बजट कम कर दिया। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि उपभोक्ता की मांग कैसे पूरी होगी। अगर बजट में दिए आंकड़ों पर भरोसा करें, तो यह बहुत बढ़िया बजट है। वित्तीय घाटा कम हुआ है। लेकिन इन आंकड़ों पर विश्वास कैसे करें? जबकि अभी कुछ समय पहले ही देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत की जीडीपी का जो नंबर है, वह ढाई फीसदी तक बढ़ाया गया है। बजट में जो बातें की गईं, इनका असर क्या होगा यह समय बताएगा। इस बजट में किसानों के लिए कोई खास घोषणा नहीं हुई जो प्रभावी हो। फिर चाहे वह जीरो बजट फार्मिंग, एग्रिकल्चर ढांचे में निवेश हो, या दस हजार उत्पादक संघ बनाने बनाने की बात। इसके साथ ही किसानों को तीन किस्तों में छह हजार देने का जो प्रावधान है, वह सकारात्मक जरूर है, पर उन किसानों को क्या जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। विदेशों से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। इससे निर्यात पर असर पड़ेगा। खुशी केवल उद्योगपति घरानों को होगी। विदेशी ऋण भी लेने की बात की गई है। लेकिन अगर विनिमय दर ऊपर-नीचे जाती है तब क्या होगा? इस वक्त कच्चे तेल की कीमत काफी कम है। आपको लगता है कि चार साल तक कुछ नहीं होने वाला है। पर अगर अमेरिका और इराक या अमेरिका-चीन के बीच चल रहे वाणिज्यिक तनाव बढ़ जाते हैं, तो सरकार की सारी गणना इधर-उधर हो जाएगी। ऐसे में अगर मुद्रास्फीति बढ़ने पर, महंगाई बढ़ जाए तो बजट के नकारात्मक असर दिखने शुरू हो जाएंगे।

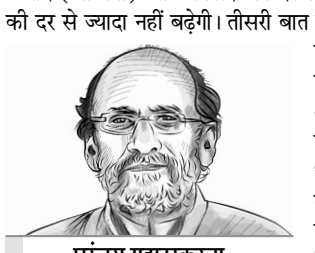

परंजय गुहाठाकुरता

मनरेगा का बजट 61 हजार करोड़ था, जिसे 60 हजार करोड़ कर दिया गया। निर्धारित लागत में भी कमी कर दी गई।

2024 के चुनाव का रोडमैप

यह पूरी तरह से एक राजनीतिक बजट है। बजट भाषण के शब्दों से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भागीदारी करने वाले मतदाताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा को 38 फीसदी (16 राज्यों में पचास फीसदी से ज्यादा) वोट मिले थे। इस बजट में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए नारे-मोदी है, तो मुमकिन है, को साबित किया गया है। इसमें महिलाओं, पानी, ग्रामीण क्षेत्र, किसान, डिजिटाइजेशन, नकदविहीन अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है, जो लोकलुभावन बजट का संकेत देता है। इसलिए यह राजनीतिक बजट है।

निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार को पूंजी बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी नकारात्मक पहलुओं और बाजार में गिरावट से परेशान नहीं होते। भले ही विपक्ष शोर मचाए, लेकिन मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार किया है। संकल्प से सिद्धि तक के अपने नारे की तरह मोदी सरकार शिलान्यास से लेकर परियोजना के उद्घाटन तक की योजना बनाती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यूपीए शासन की तरह देश में नीतिगत अपंगता न हो। नोटबंदी और जीएसटी की तरह बैंक से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से ज्यादा निकालने पर टैक्स लगाने की बात से यही संकेत मिलता है कि यह एक राजनीतिक हथियार है। इसका कारण यह है कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में धन बल और वोट के लिए पैसे वितरण की कुप्रथा में कमी लाना चाहती है। दक्षिण भारत के ज्यादातर राजनेताओं ने वोट के लिए 2,000 रुपये के नोट मतदाताओं को घूस के रूप में दिए। इसमें कमी आएगी। इस बार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जो 21वीं सदी में देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। इस बजट को बहुत सारी आशाओं और आकांक्षाओं वाला बजट माना जाता है। निर्मला सीतारमण ने जो बजट भाषण पढ़ा, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के विचार, भाजपा के 2019 के घोषणा पत्र के प्रमुख हिस्से समाहित हैं। इस बजट में कई योजनाएं शामिल हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किया था। मोदी की कई विदेश यात्राओं की दृष्टि और अपेक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रवासी भारतीय को भारत आने पर आधार कार्ड देना और उन्हें भारत में स्टार्ट अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रतिभा पलायन रोकने के लिए इस बजट में छात्रों को भारत में ही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की बात कही गई है। इसमें महिलाओं पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए एक लाख रुपये के ओवरड्राफ्ट का प्रावधान गेम चेंजर साबित हो सकता है।

आर राजगोपालन

वरिष्ठ पत्रकार

वित्त मंत्री ने एफडीआई आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने नागरिक उड्डयन, मीडिया, एनिमेशन और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा में ढील देने के इरादे की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, क्योंकि मोदी सरकार विकास को बढ़ावा देने के उपाय तलाश रही है। इस बजट में 50-60 से ज्यादा नए मार्ग सुझाए गए हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नागरिक उड्डयन, मीडिया, एनिमेशन और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा में ढील देने के सरकार के इरादे की भी घोषणा की। उन्होंने एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को भी आसान बनाने का वादा किया। इस समय बीमा क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई है, जबकि विमानन क्षेत्र में यह 49 फीसदी से 100 फीसदी के बीच है। मीडिया क्षेत्र में प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा जहां 26 फीसदी है, वहीं एफएम रेडियो में 49 फीसदी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजग सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 'न्यू इंडिया' के लिए काम करना शुरू किया था। इसके लिए कार्यक्रमों को तेज किया जाएगा और लालफीताशाही को कम किया जाएगा।

निवेश और खर्च बढ़ाने की जरूरत

बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है, सिर्फ घोषणाएं नहीं होती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट भाषण में आंकड़े नहीं दिए गए हैं कि कहां से कितना राजस्व आएगा और उसे किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च किया जाएगा। बजट में तो आंकड़े दिए गए होंगे, लेकिन बजट भाषण में उसका जिक्र नहीं किया गया। शायद वित्त मंत्री को लगा होगा कि इससे बाजार पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए आंकड़ों का बजट भाषण में खुलासा नहीं किया गया।

बजट की मुख्य बातों में कहा गया है कि अनुमानित जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार 12 फीसदी होगी, जबकि आज वह बढ़ रही है कोई आठ फीसदी की रफ्तार से। इसका मतलब है कि हमने अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान कुछ ज्यादा ही लगा लिया है। उस वजह से राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान भी ज्यादा कर लिया। तो अगर राजस्व में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, जितना बजट में बताया जा रहा है, तो फिर हम खर्च घटा देंगे, क्योंकि राजकोषीय घाटा को 3.3 फीसदी पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। जब हम खर्च घटा देते हैं, तो जो जरूरी खर्च हैं, उन्हीं में ज्यादा कटौती होती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को जो फायदा होना चाहिए था, वह नहीं मिलेगा।

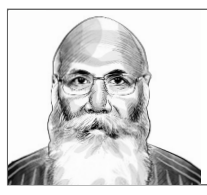

अरुण कुमार

आर्थिक विश्लेषक

अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, तो खर्च बढ़ाने की जरूरत है। खर्च हम तभी बढ़ा सकते हैं, जब हमारे पास राजस्व के साधन हों। उसके लिए जीएसटी में फेरबदल नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष कर में ही कुछ फेरबदल किया जा सकता था। लेकिन प्रत्यक्ष कर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे राजस्व बढ़ाया जा सकता था। पेट्रोल-डीजल पर सेस बढ़ाया गया है, लेकिन उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो निम्न और मध्य वर्ग को विभिन्न योजनाओं (हाउसिंग आदि में) के जरिये फायदा पहुंचाने की जो बात की जा रही है, उसे भी उतना फायदा नहीं पहुंचेगा। जैसे हाउसिंग के ब्याज पर छूट दी गई है, पर घर तो लोग रोज खरीदते नहीं हैं और जो घर खरीदेगा, उसी को फायदा होगा, बाकी आम जनता को तो महंगाई बढ़ने से नुकसान ही होगा। आम जनता को तो फायदा तभी मिलेगा, जब विकास दर बढ़ेगी, मुद्रास्फीति कम होगी।

सरकार पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि यह कैसे होगा। अगर आज हमारी वास्तविक विकास दर 5.8 फीसदी है, तब तो ऐसा होना संभव नहीं लगता। सरकार ने एक अजीब व्यवस्था बताई है कि वह आठ फीसदी वास्तविक विकास दर रखेगी और चार फीसदी मुद्रास्फीति की विकास दर रखेगी, तो इस तरह विकास दर बारह फीसदी हो जाएगी, तो हम पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है, तो हमें यह कहना चाहिए कि आज दो लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था है और हम इसे 375 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। यह बहुत अवास्तविक लक्ष्य है। इस बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, लेकिन उसमें विजन की कमी है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कहा गया कि हम युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे, जिससे कि वे विदेश जा सकें। अब कौन- सी उन्नत या बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी प्रतिभा का निर्यात करती है! किसानों की आय दोगुनी करना भी संभव नहीं लग रहा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा, जो अभी तक ढंग से लागू नहीं होता। ऐसी घोषणाओं के लिए ठोस उपाय होने चाहिए, पर सरकार के पास साधनों की भी कमी है।

अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत है। खर्च तभी बढ़ा सकते हैं, जब राजस्व के साधन हों। उसके लिए प्रत्यक्ष कर में ही कुछ फेरबदल किया जा सकता था।